विचार

> 2014 के बाद भारत ने सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ करीबी संबन्ध स्थापित किए हैं।

संपादकीय

जीपीएस नहीं, 'नाविक' बोलिए

मार-धाड़, दंगा-फसाद, साम्प्रदायिक तनाव, नेताओं की उल-जलूल राजनीतिक जुमलेबाजी, सीमा पर अशांति और भारत-पाक के बीच तनाव की थकी-पिटी और उबाऊ ख़बरों के बीच एक सूकून देने वाली खबर आई है, खबर है कि अगर सब कुछ ठीक-ठाक चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब आप अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन पर विदेशी तकनीकी वाले जीपीएस की मदद से रास्ता नहीं खोजेंगे बल्कि आपके मोबाइल में स्टाल होगा एक विशुद्ध भारतीय रास्ता खोजी एप जिसके जरिए आप रास्ता खोजते नजर आयेंगे। जीपीएस के विकल्प वाले इस नए एप का नाम है 'नाविक'। हम भारतीय नाविक शब्द से अच्छी तरह परिचित हैं। नाव से नदी पार करवाने व्यक्ति को नाविक कहा जाता है और मिथकीय आख्यानकों पर यकीन करें तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नाव से नदी पार ले जाने वाले केवट भी एक नाविक ही थे। वैसे तो हवा में दिशा ज्ञान देने वाले यन्त्र को कुतुबनुमा कहा जाता है लेकिन यहां मामला जमीन पर राह दिखाने से जुड़ा है इसलिए इसे नदी पार करने के समकक्ष मान कर इसका नाम नाविक दिया गया है वैसे भी विमान के अलावा जल और जमीन के रास्ते सफ़र करने वाले परिवहन के इन दोनों साधनों को सतह परिवहन यानी सरफेस ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसलिए जीपीएस के भारतीय विकल्प को भी शायद नाविक नाम दिया गया है।

खबर पक्की है कि बस कुछ दिन बाद ही, संभवतः अगले महीने नवम्बर से ही जीपीएस के बदले हमारा नाविक रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। नाविक का आविष्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा किया गया है। पिछले दिनों भारतीय मोबाइल कांग्रेस में स्मार्ट फ़ोन से चलने वाले 'नाविक' का पहला प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर इसरो ने बताया कि अमेरिकी कंपनी क्वालकॉम ने उसके साथ मिलकर अपना नया चिपसेट प्लेटफॉर्म विकासित और उसका परीक्षण किया है। यह नया नेविगेशन सिस्टम इसरो द्वारा स्थापित उपग्रहों के तंत्र पर काम करता है जो भारतीय उपमहाद्वीप में जीपीएस के विकल्प के रूप में काम करेगा। मोबाइल कंपनियों के लिए यह चिपसेट इस साल नवंबर से उपलब्ध होगा। कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय उप महाद्वीप तक के सीमित क्षेत्रफल तक प्रभावशील हमारी यह तकनीकी क्षमता अपनी सीमाओं के बावजूद देश के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की हमारी सोच को गति देने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विगत सोमवार 14 अक्टूबर को संपन्न इस मोबाइल कांग्रेस में 30 देशों की 500 से ज्यादा कंपनियों ने मोबाइल हिस्सा लिया था

ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) एक उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणाली है जिसका प्रयोग किसी भी चीज की लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता हैं यह कम से कम 24 उपग्रहों से बना है। GPS किसी भी मौसम में 24 घंटे काम करता है। जीपीएस तकनीक का उपयोग पहली बार 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था और अगले कुछ दशकों में इसका विस्तार 1980 में नागरिकों के लिए किया गया। आज, जीपीएस रिसीवर कई वाणिज्यिक उत्पादों, जैसे ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, व्यायाम घड़ियों और जीआईएस उपकरणों में शामिल हैं। यह तकनीकी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है इसका इस्तेमाल मोबाइल, हवाई जहाज, रेल, बस और गाडियों में होता है यह ट्रांसपोर्टे में ज्यादा इस्तेमाल होता है इसकी मदद से हम कहीं का भी रास्ता बड़ी आसानी से पता कर सकते है हम अपनी लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन की दूरी भी बड़ी आसानी से पता कर सकते है । यहां यह समझना भी जरूरी होगा कि जीपीएस के बारे में तो यह पता है कि यह अंगरेजी के तीन शब्दों ग्लोबल, पोजिशनिंग और सिस्टम का संक्षिप्तीकरण है, जिसका मतलब यह भी है कि किसी स्थान (Location) की स्थिति (Position) का कैसे निर्धारण किया जाता है और नाविक भी यही काम करेगा तो इसे जीपीएस का विकल्प कैसे कह सकते हैं। दोनों की तकनीक तो एक ही है फिर फर्क क्या है, क्या केवल नाम देने भर से किसी वैज्ञानिक तकनीक पर हमारा या किसी का आधिपत्य हो सकता है?

प्रसंगवश गौरतलब यह भी है कि जीपीएस में पृथ्वी की सतह से लगभग 12,000 मील (19,300 किलोमीटर) ऊपर अंतरिक्ष में तैनात 24 उपग्रह शामिल हैं। वे हर 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 7,000 मील प्रति घंटे (11,200 किलोमीटर प्रति घंटे) की बेहद तेज गति से होती है। उपग्रहों को समान रूप से फैलाया जाता है ताकि चार उपग्रह विश्व में कहीं से भी सीधी रेखा के माध्यम से सुलभ हो, प्रत्येक जीपीएस उपग्रह एक संदेश प्रसारित करता है जिसमें उपग्रह की वर्तमान स्थिति, कक्षा और सटीक समय शामिल होता है। एक जीपीएस रिसीवर कई सैटेलाइटों से प्रसारण को जोड़कर त्रिकोणासन नामक प्रक्रिया का उपयोग करके इसकी सही स्थिति की गणना करता है। रिसीवर के स्थान को निर्धारित करने के लिए तीन उपग्रहों की आवश्यकता होती है, हालांकि चार उपग्रहों का कनेक्शन आदर्श है क्योंकि यह अधिक सटीकता प्रदान करता है।

दुनिया में जीपीएस के समान अन्य सिस्टम हैं, जिन्हें सभी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। GLONASS रूस द्वारा निर्मित एक उपग्रह तारामंडल प्रणाली है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी गैलीलियो का निर्माण कर रही है, जबकि चीन BeiDou का निर्माण कर रहा है। अधिकांश गार्मिन रिसीवर्स ग्लोनास और जीपीएस दोनों को ट्रैक करते हैं, और कुछ BeiDou को ट्रैक करते हैं। जीपीएस उपग्रहों के बारे में कुछ कई रोचक तथ्य हैं । मसलन GPS के लिए आधिकारिक USDOD का नाम NAVSTAR है, पहला जीपीएस उपग्रह 1978 में लॉन्च किया गया था।1 994 में 24 उपग्रहों का एक पूर्ण नक्षत्र हासिल किया गया था। प्रत्येक उपग्रह का निर्माण लगभग 10 वर्षों तक होता है। रिप्लेसमेंट लगातार कक्षा में निर्मित और लॉन्च किए जा रहे हैं। एक जीपीएस उपग्रह का वजन लगभग 2,000 पाउंड है और सौर पैनलों के विस्तार के साथ लगभग 17 फीट है। जीपीएस उपग्रह सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं, लेकिन सूर्यग्रहण के मामले में उनके पास बैकअप बैटरी ऑनबोर्ड होती है और ट्रांसमीटर की शक्ति केवल 50 वाट या उससे कम है।

आज का इतिहास

1931	प्रसिद्ध हिन्दी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ।
1939	हिन्दी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलन का जन्म हुआ।
1945	फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला।
1950	बेल्जियम में मृत्यु दंड समाप्त हुआ।
1998	अमेरिका की कैंसर विशेषज्ञ डॉ. जेन हेनी औषधि एवं खाद्य प्रशासन (एफडीए) की पहली महिला आयुक्त बनीं।
2005	सामूहिक बलात्कार की शिकार पाकिस्तान के मुख्तारन माई 'वूमैन ऑफ द इयर' चुनी गईं।
2012	भारतीय फिल्म निर्माता-निर्देशक यश चोपड़ा का निधन हुआ।
2013	कनाडा की संसद ने मलाला युसफजई को कनाडा की नागरिकता प्रदान की।

पश्चिम एशिया के सन्दर्भ में भारत के बदलते प्रतिमान

जतिन कुमार

> पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सामरिक रिश्तों के बावजूद, आजादी के बाद भारतीय विदेश नीति में इन देशों को मात्र कच्चे तेल के निर्यातक के रूप में ही महत्व दिया गया। भारत ने पश्चिम एशियाई देशों जैसे इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, ईरान तथा फिलिस्तीन के विषय पर एक संतुलनात्मक नीति का अनुसरण किया तथा सीमित दायरे में ही रिश्तों का विस्तार किया। जिसकी वजह से सामरिक रूप से अतिमहत्वपूर्ण होने के बावजूद 2015 तक ये देश भारतीय प्रधानमंत्रियों के विदेशी दौरों से दूर रहे।

सामरिक रूप से पश्चिम एशिया भारत की विदेश नीति मे एक मुख्य स्थान रखता है। विश्व के मानचित्र में पश्चिम एशियाई देशों की भूगोलिक स्थिति तथा इनका तेल एवं गैस से संपन्न होना भारत की ऊर्जा सम्बंधित जरूरतों की नज़र से महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद से ही पश्चिम एशियाई देश भारत की ऊर्जा संबन्धित जरुरतो को पुरा करने मे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे है। यह क्षेत्र भारत की तेल एवं गैस आवश्यकता के 60 प्रतिशत से अधिक भाग का स्रोत है जो ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतना नही राष्ट्रीय सुरक्षा की नजर से भी पश्चिम एशियाई देशो, खासकर इस्रायल, से भारत कि दोस्ती सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने मे अहम रही है। इस क्षेत्र के साथ भारत के घनिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सभ्यतागत सम्बन्धो दोनों के रिश्तों नीव की भूमिका अदा की है। इस क्षेत्र के साथ भारत के सभ्यतागत संपर्क लिखित इतिहास की शुरूआत से ही चले आ रहे हैं। प्राचीनकाल में सिंधु/डिल्मन सभ्यता के समय से दोनों पक्षों के बीच सतत रिश्ते रहे तथा आधुनिक काल में उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों ने साझा लड़ाई बह लड़ी है। पश्चिम एशियाई देशो के साथ भारत के बहुआयामी संबंध को मधुर बनाने मे इस क्षेत्र में रह रहे 7 मिलियन से अधिक भारतीयो ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जो हर साल धन प्रेषण के रूप में लगभग 40 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान करते हैं। भारत सरकार की मिनस्ट्री ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार 2018-19 में इस क्षेत्र के साथ भारत का कुल व्यापार 1,21,337.65 मिलियन अमरीकी डालर रहा है जोकि इस क्षेत्र की व्यापारिक अहमियत को दर्शाता है।

किन्तु पश्चिम एशियाई देशो के साथ भारत के ऐतिहासिक और सामरिक रिश्तो के बावजूद, आजादी के बाद भारतीय विदेश निति में इन देशो को मात्र कच्चे तेल के निर्यातक के रूप में ही महत्व दिया गया। भारत ने पश्चिम एशियाई देशो जैसे इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इराक, ईरान तथा फिलिस्तीन के विषय पर एक सन्तुलनात्मक निति का अनुसरण किया तथा सिमित दायरे में ही रिश्तो का विस्तार किया। जिसकी वजह से सामरिक रूप से अतिमहत्वपूर्ण होने के बावजूद 2015 तक ये देश भारतीय प्रधानमंत्रियों के विदेशी दौरों से दूर रहे। किन्तु गत कुछ वर्षो में इन देशो के सन्दर्भ में भारत की निति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'लिंक वेस्ट' निति के तहत, भारत ने पश्चिम एशियाई देशो के साथ सम्बन्धो को खास अहमियत दी। ऐसा नहीं है कि ये देश पहले भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं थे किन्तु परंपरागत संतुलनात्मक नीति कारण व्यक्तिगत स्तर पर सम्बन्धो में घनिष्टता का आभाव था। किन्तु 'लिंक वेस्ट' नीति के तहत भारत ने इन देशों के सन्दर्भ ने एक अतिसक्रीय नीति का अनुसरण किया जिसने बहुत ही तेज़ी से भारत को प्रमुख पश्चिम एशियाई देश जैसे इस्राइल, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के बहुत नज़दीक ला खड़ा किया है। प्रधानमंत्री मोदी की 16 अगस्त 2015 को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा ने यह पूरी तरह से रेखांकित कर दिया की भारत, पश्चिम एशियाई के सन्दर्भ में अपनी पुरानी निति का अनुसरण नहीं करने वाला है। यह यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पिछले 34 सालो में पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशो ने $75 बिलियन के इंफ्रास्ट्रचर बिल्ड़गि फण्ड पर सहमति बनाई थी। इसके बाद जनवरी 2017 में शेख मोहम्मद बिन ज़ायेद अल- नाह्यान अबू धाबी के युवराज तथा यूएई (UAE) के सैन्य बलों के डेप्युटी सुप्रीम कमांडर ने भारत की यात्रा की तथा वह गणतंत्र दिवस समाहरो में भारत के मुख्य अतिथि रहे। इसी यात्रा के दौरान दोनों देशो ने सात महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमे साइबर सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रचर में निवेश, इन्शुरन्स तथा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आम सहमति शामिल थे।

संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की (14-16 नवंबर 2015), सऊदी अरब (2-3 अप्रैल 2016), ईरान (22-23 मई 2016), क़तर (4-5 जून 2016)इस्राइल (4-5 जुलाई 2017), बहरीन (22-26 अगस्त 2019), ओमान तथा फिलिस्तीन (9-12 फरवरी 2018) की यात्राएं की जोकि भारत के लिए पश्चिम एशियाई देशो की बढ़ती प्राथमिकताओ को दर्शाता है। जहा प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी यात्राओं के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात व सऊदी अरब के साथ भारत के सम्बन्धो को एक नई दिशा दी, वही 68 सालों बाद इजराइल यात्रा ने भारत-इस्राइल सम्बन्धो खुल्ले रूप से स्वीकार कर, द्विपक्षीय सम्बन्धो के एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। आजादी के बाद से भारत आंतरिक व अंतराष्ट्रीय राजनीतिक उठा पटक के कारण कभी इस्राइल के साथ अपने सम्बन्धो को खुल्ले रूप से स्वीकार नहीं कर पाया था। किन्तु 68 सालो बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहली इस्राइल यात्रा ने यह साफ़ कर दिया की भारत अब इस्राइल के साथ अपने सम्बन्धो को अब खुल तौर पर तथा गौरव के साथ स्वीकार करेगा। इस्राइल यात्रा ने जहा द्विपक्षीय सम्बन्धो को एक नई दिशा दी, वही पश्चिम एशियाई निति में इस्राइल को एक आम देश की तरह सामान्यीकरण भी किया। इराकी कुर्दिस्तान के विषय पर भी भारत की नीति में बदलाव की सम्भावनाए उस समय बनने लगी जब 2014 में भारत के स्पेशल राजदूत सुरेश क़े. रेड्डी ने इराकी कुर्दिस्तान की यात्रा की इससे पहले भारत ने कुर्दिस्तान के साथ सिमित कूटनीतिक रिश्तों की नीति का ही अनुसरण किया था। अपनी यात्रा के दौरान रेड्डी ने कहा कि 'भारत इस कठिन समय में कुर्दिस्तान क्षेत्र समर्थन करता है' तथा यह विश्वास भी जाहिर किया की पेशमेरगा बल क्षेत्र में स्थिरता लाने में सफल रहेंगे।

यह भारत की अतिसक्रीय पश्चिम एशिया नीति का ही परिणाम था की अबु धाबी में आयोजित ऑर्गनाइज़ेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC) की 46वीं बैठक में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को 'गेस्ट ऑफ़ ऑनर' के तौर पर विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिये आमंत्रित किया गया। यह पहला मौका था जब 57 सदस्यों वाले OIC के मंच पर भारत पिछले करीब 50 वर्षों के इतिहास में पहली बार शामिल हुआ। यह भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा खाड़ी के देशों के साथ घनिष्ट होते सम्बन्धो बात का जीवंत उदाहरण था। जहां बालाकोट में आतंकी गुटों पर भारतीय हमले के बाद, पाकिस्तान के दबाव के बावजूद भारत को अपनी बात रखने का मौका दिया गया।

वास्तव में 2014 के बाद भारत ने सऊदी अरब तथा संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ करीबी सम्बन्ध स्थापित किये है। सऊदी अरब के द्वारा एयर इंडिया की इस्राइल जाने वाली फ्लाइट्स को अपने हवाई क्षेत्र से जाने देने की अनुमति देना दोनों देशो के बीच तेज़ी से मधुर होते सम्बन्धो का परिचायक हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्यूंकि इन देशों को पाकिस्तान का करीबी माना जाता रहा है। पिछले 50 सालों में पाकिस्तानी कूटनीति ने भारत को इस्लामिक देशों से अलग-थलग करने की निरंतर कोशिश की है इस सन्दर्भ में भी यह भारत की विदेश नीति की सफलता है कि लगभग सभी पश्चिम एशियाइ इस्लामिक देशों के साथ भारत मज़बूत संबंध स्थापित करने में सफल रहा है। भारत ने पश्चिम एशिया के देशों जैसे-इजरायल, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की ओर संबंधों के विस्तार की जो नीति अपनाई है, उसे यह साफ़ प्रतीत होता है, कि भारत इन देशों के प्रति संतुलन रखने की अपनी परंपरागत नीति अब को बदल चूका है। वह सभी पश्चिम एशियाई देशो के साथ सामाजिक, आर्थिक, तथा सांस्कृतिक रिश्तो में विकास करने का इच्छुक है तथा आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में सभी के साथ कंधे से कन्धा मिलाकर आगे बढ़ना चाहता है।

साथ ही उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की के 'एकतरफा सैन्य कार्रवाई'की निंदा से यह भी स्पष्ट किया है कि वह किसी भी देश की सम्प्रभुता पर हमले परिस्थिति में निर्भीक आवाज उठाने में भी सक्षम है। भारत की सक्रिय निति अभी तक तो बेहद कामयाब रही है परन्तु आने वाले समय में क्षेत्रीय ताकतों तथा अपनी शक्तियों एवं सीमाओं की वास्तविकता को ध्यान में रखकर ही नीतियों का निर्धारण करना होगा। इस समय पश्चिम एशियाई देशो में जो अस्थिरता का जो मौहौल है वो भारत की विदेश निति की कड़ी परीक्षा लेगा।

एक ऊंघते हुए देश में आशंकित क़त्ल होने में हैरानी क्या ?

विजय कपूर

अगर बाद में गलत नहीं साबित होतीं [जैसा कि अक्सर होता है] तो फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी हत्याकांड में अपनी ही पीठ थपथपाने में मशगूल है। इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय तक, तिवारी का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था,लेकिन यूपी पुलिस के मुताबिक़ उसने 24 घंटे के अंदर ही केस को सुलझा लिया। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने शनिवार को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुजरात का रशीद पठान नाम का शख्स इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस के मुताबिक़ इस मामले में अब तक तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इनके नाम हैं-रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान।

रशीद अहमद पठान 23 साल का है। यूपी पुलिस के मुताबिक रशीद अहमद पठान को कम्प्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान है,लेकिन ये पेशे से दर्जी का काम करता है। जबकि हिरासत में लिए गए दूसरे शख्स मौलाना मोहसिन शेख की उम्र 24 साल है और ये शख्स एक साड़ी की दुकान में काम करता है। तीसरे शख्स का नाम फैजान है और इसकी उम्र 21 साल है। ये शख्स भी सूरत में रहता है और ये जूते की शॉप में नौकरी करता है ।पुलिस का कहना है कि उसने अपनी छानबीन में पाया है कि कमलेश तिवारी हत्याकांड के आरोपियों ने सूरत में ही भगवा कुर्ता सिलवाया था। इसे पहनकर आरोपी लखनऊ आए और कत्ल को अंजाम दिया। पुलिस की यह कहानी सही ही होगी,जब तक कोई नई हकीकत सामने नहीं आती। मगर सवाल है जितनी तेज रफ्तार और चौंकन्नेपन के साथ पुलिस ने हत्या के बाद अपनी ड्यूटी निभाई, आखिर क्या कारण है कि सुरक्षा संबंधी किसी खौफनाक दुर्घटना के पहले वह इससे एक तिहाई चौंकन्नापन भी क्यों नहीं दिखा पाती? इसी मामले में देखिए हत्यारा कितनी सहजता से आकर एक ऐसे शख्स की हत्या करके चले जाते हैं जिसे पुलिस के दो-दो गनर मिले हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि ऐसा तब हो जाता है जबकि उसे लगातार इसकी आशंका सता रही होती है और मकतूल अपनी सुरक्षा को और बेहतर किए जाने की मांग कर रहा था।

लेकिन उसकी इस आशंका पर कोई कान देने की बात तो दूर यूपी पुलिस ने कमलेश तिवारी को दो ऐसे सुरक्षाकर्मी उपलब्ध करा रखे थे, जो शरीर से थके और फर्ज से गैर ईमानदार थे। अगर ऐसा न होता तो दरवाजे पर गनर की मौजूदगी के बावजूद महज कट्टा और चाकुओं से दो गैर पेशेवर हत्यारे तिवारी को इस तरह मारकर न चले जाते। हत्यारे आते हैं, कमलेश तिवारी के पैर छूते हैं, किसी भूली-बिसरी गलती की खुद ही याद दिलाकर माफी मांगते हैं, शिकार व्यक्ति उन्हें चाय पिलाता है, नाश्ता कराता है, पान सिगरेट कराता है। यह सब करके हत्यारे उठते हैं और बड़े आराम से धायं धायं करके गोली मार देते हैं।

सिर्फ गोली ही नहीं मारते। बड़े इत्मीनान से एक दो नहीं चाकू से कोई पन्द्रह वार करते हैं। यह न केवल एक वीभत्स कृत्य है बल्कि जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया उससे दो ही बातें अनुमान तक जाती हैं कि या तो कोई मिलीभगत होगी या हत्यारों को यकीन था कि दरवाजे पर बैठा अधेड़ पुलिसवाला यह सब नहीं सुनेगा। इसलिए उन्हें कतई जल्दी नहीं थी न ही हडबडी। वह आराम से एक वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देकर निधडक निकल जाते हैं। इसके बाद भी डीजीपी ओपी सिंह कहते हैं कि कमलेश तिवारी की सुरक्षा के संबंध में कतई लापरवाही नहीं बरती गई। उन्हें पूरी सुरक्षा दी गई थी। जबकि पुलिस ने इस हत्याकांड में खुद पाया है कि कमलेश की सुरक्षा में तैनात दीवान मुसाफिर प्रसाद को उनकी हत्या के बारे में कोई खबर ही नहीं थी। यहां तक कि उसने न ही गोली की आवाज सुनी और न ही किसी को भागते हुए देखा।

एक पुलिसवाले से ज्यादा सजग तो कमलेश तिवारी के मकान के ऊपरी हिस्से में रहने वाली एक किरायेदार नीतू सिंह रही, जिसने गोली की आवाज सुनी और पुलिस की जांच टीम को इसकी जानकारी भी दी। जबकि यह पुलिस की ही जांच रिपोर्ट कहती है कि जब इस सम्बन्ध में आला अधिकारियों ने दीवान से पूछताछ की तो वह कोई जवाब नहीं दे पाया। उसके मुताबिक उसने न तो गोली की कोई आवाज सुनी न ही किसी को भागते हुए देखा, लेकिन घटनास्थल से मिले सीसीटीवी तस्वीरों में साफ़ दिख रहा है कि हत्यारे भगवा कुर्ता में पूरी इत्मीनान में थे। गुजरात एटीएस के डीआईजी हिमांशु शुक्ला के मुताबिक हिरासत में लिए तीनों आरोपियों ने इस कत्ल में अपनी भागीदारी कबूल कर ली है। इस तरह यूपी पुलिस और गुजरात एटीएस ने इन तीनों मोहसिन शेख, फैजान और रशीद पठान को हिरासत में ले लिया है।

पुलिस कितनी लापरवाह है इसकी पुष्टि पुलिस के दावों से ही हो जाती है। डीजीपी ने ओपी सिंह के मुताबिक़ कमलेश तिवारी के परिजनों को पहले से ही मौलाना अनवारुल हक और मुफ्ती नईम काजमी पर इस तरह की किसी घटना के अंजाम देने का अंदेशा था। कमलेश तिवारी ने खुद पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हुए इन दोनों से खुद को खतरा बताया था,लेकिन तब पुलिस ने एक न सुनी थी और आज खुद बिना इस बात के झिझक के कि सुरक्षा को लेकर कमलेश तिवारी का डर सही और पुलिस का रवैय्या लापरवाही भरा था, पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसने 24 घंटे में केस को क्रैक कर लिया। सूरत लखनऊ और बिजनौर की जिस कड़ी को पुलिस जोड़कर वाहवाही चाह रही है,वह उसकी उपलब्धि नहीं बल्कि अफ़सोस का विषय है कि तमाम आशंकाओं के बाद हत्या को टाला न जा सका।

अब डीजीपी ओपी सिंह ने कह रहे हैं कि कमलेश तिवारी की हत्या का कारण साल 2015 में उनके द्वारा दिया गया विवादित भाषण हो सकता है। लेकिन यह आशंका तो कमलेश के घर वालों और खुद कमलेश तिवारी को भी थी, फिर पुलिस को तब ऐसा क्यों नहीं लगा,जब मकतूल इसी के चलते सुरक्षा की मांग कर रहा था।वास्तव में अभी तक पुलिस ने संदिग्धों की जिन बातों का खुलासा किया है।उससे लगता है कि यह वास्तव में रेडिकल किलिंग का ही मामला है जो इस ऊंघते हुए देश में कभी मुश्किल नहीं होता।

[लेखक वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं]

-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

'फॉर हूम द बेल टोल्स' दूसरे विश्व युद्ध के पहले उपन्यास का 80वां साल

अभय कुमार 'अभय'

साल 1947 में भारत के विभाजन के बाद लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हुए, दंगे हुए, जिनमें बड़ी तादाद में हत्याएं व अन्य प्रकार की हिंसा हुई। यह भयंकर मानव त्रासदी थी, जिसे उस दौर के संवेदनशील लेखक नजरंदाज नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि सआदत हसन मंटो, भीष्म साहनी, अमृता प्रीतम आदि ने विस्थापन के त्रासदी पर अपनी कलम चलायी और पूरी दुनिया को उन मानवीय संवेदनाओं से परिचय कराया जो इस त्रासदी की उपज थीं। 1947 से पहले दुनिया ने पहले व दूसरे विश्व युद्धों के रूप में दो और दिल दहलाने वाली त्रासदियां देखी थीं, जिन्होंने विशेषरूप से यूरोप (और जापान) में जीवन को प्रभावित किया था। इसलिए यह आश्चर्य नहीं है कि युद्ध-विरोधी पुस्तकें बड़ी संख्या में प्रकाशित हुईं। इन्हीं किताबों की भीड़ में जो एक उपन्यास, मेरी दृष्टि में, एकदम अलग खड़ा नजर आता है और आज 79 वर्ष बाद भी अपना महत्व बनाये हुए है, वह अर्नेस्ट हेमिंग्वे का 'फॉर हूम द बेल टोल्स' (जिसके लिए बजती हैं घंटियां) है।

यह एक प्रेम व विरह, जीवन व मृत्यु की कथा है। अक्टूबर 1940 में जब यह प्रकाशित हुआ था तो 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने इसे स्पेनी गृह युद्ध पर 'सबसे प्रभावी दस्तावेज' बताते हुए 'दूसरे विश्व युद्ध पर पहला प्रमुख उपन्यास' घोषित किया था। हेमिंग्वे ने नार्थ अमेरिकन न्यूजपेपर एसोसिएशन के लिए स्पेनी गृह युद्ध की रिपोर्टिंग की थी और अपनी रिपोर्टों में उन्होंने युद्ध के विनाशक प्रभावों को उजागर किया था। स्पेन में जब फ्रांसिस्को फ्रांको व अन्य जनरलों ने 1936 में सत्तारूढ़ उदार रिपब्लिकन सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था तो गृह युद्ध छिड़ गया था। तीन वर्ष तक फ्रांको की सेना को रिपब्लिकन/लोयलिस्ट व साम्यवादी गठबंधन सेना ने रोके रखा, जिनमें कम्युनिस्ट इंटरनेशनल द्वारा स्थापित इंटरनेशनल ब्रिगेड, पैरामिलिट्री यूनिट भी थे। लेकिन जर्मनी व इटली के फासीवादियों से मदद लेकर राष्ट्रवादी जीत गये और उन्होंने आतंक का वह तांडव खेला जो युद्ध के बाद भी जारी रहा।

इस पृष्ठभूमि में हेमिंग्वे रोबर्ट जॉर्डन की कहानी लिखते हैं, जो एक अमेरिकन हैं और इंटरनेशनल ब्रिगेड में विस्फोट प्रयोग करने वाले के रूप में शामिल हैं। वह स्पेनिश सिएरा में फासीवाद-विरोधी गुरिल्ला यूनिट से जुड़े हैं और उन्हें राष्ट्रवादियों के लिए महत्वपूर्ण एक पुल को उड़ाना है ताकि रिपब्लिकन फौज आगे बढ़ सकें। लगभग 500 पृष्ठों के उपन्यास में मोंटाना में स्पेनिश भाषा के प्रोफेसर जॉर्डन जान जाते हैं कि युद्ध के खतरे क्या हैं और आखिरकार उससे करीबी दोस्तियां कैसे बनती हैं। पहाड़ों में देवदार के जंगलों में जॉर्डन की मुलाकात मारिया से होती है, जो भयंकर उत्पीड़न का सामना करके फ्रांको के विद्रोहियों से बचकर भागी है। जॉर्डन मारिया के प्रति आकर्षित हैं, लेकिन उद्देश्य खोये हुए हैं, इसलिए जीवन, मृत्यु, युद्ध व राजनीति से संबंधित प्रश्नों से संघर्ष करते हैं।

जॉर्डन जल्द ही अपने को पाब्लो व उनकी शक्तिशाली पत्नी पिलर के गुरिल्ला गुट से जोड़ लेते हैं। उनसे सवाल होता है कि क्या वह कम्युनिस्ट हैं? जिसके जवाब में वह कहते हैं, "नहीं, मैं फासीवाद-विरोधी हूं।" पिलर जिज्ञासू हो जाती है और मालूम करती है, "कितने लम्बे समय से?" वह कहते हैं, "जब से मैंने फासीवाद को समझा है।" पाब्लो शुरू में ब्रिगेड मिशन का हिस्सा नहीं बनना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि फासीवादी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे सब सदस्य जुड़ जाते हैं। बहरे के नाम से विख्यात अल सोर्दो को जटिल योजना पर शंका है जो कागज पर तो साधारण लगती है, लेकिन जैसा जॉर्डन जानते हैं कि 'कागज कम खून बहाता है'। फिजा में अनिश्चितता है, कुछ पल साथ रहने के लिए चुराकर जॉर्डन व मारिया सिर्फ प्रेम व खुशी की बातें कर सकते हैं, "...इस बीच जितना भी तुम्हारे पास है या कभी हो सकता है वह आज, रात, कल, आज, रात, कल ...उसने सोचा और इसलिए जो समय मिले उसे ले लो और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हो।"

ऐसी व्याख्याएं- 'तुम्हारा राष्ट्रवाद और तुम्हारी राजनीति उस समय दिखायी नहीं दी जब तुम मर गये' और जॉर्डन व मारिया के बीच अच्छे दिनों की विश्वास करने योग्य वार्ता हमें अंतिम युद्ध की ओर ले जाती है। फासीवादियों को आक्रमण की हवा लग जाती है और वह तैयार हैं, जॉर्डन कमांडर को संदेश भेजते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। "रोबर्ट जॉर्डन ने उन्हें वहां ढलान के करीब देखा था, अब उनके करीब, और नीचे उन्होंने सड़क को देखा और पुल को और उसके नीचे वाहनों की लम्बी कतार को। अब वह पूरी तरह आत्मसात हो चुके थे और उन्होंने हर चीज को देर तक अच्छी तरह से देखा।"

अब कुछ इस उपन्यास के शीर्षक के बारे में हो जाये। शुरू में इसे 'द अनडिस्कवर्ड कंट्री' नाम दिया गया था, जिससे हेमिंग्वे खुश नहीं थे। आखिरकार हेमिंग्वे को जिसकी तलाश थी वह उन्हें 'द ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्स' में मिल गया। जॉन डॉन की पंक्तियां- 'कोई व्यक्ति द्वीप नहीं है --- हर व्यक्ति महाद्वीप का हिस्सा है, मुख्य का अंश ... किसी भी व्यक्ति की मृत्यु मुझे छोटा कर देती है क्योंकि मैं मानवता से जुड़ा हूं और इसलिए यह जानने का प्रयास नहीं किया कि किसके लिए घंटियां बजती हैं। यह तुम्हारे लिए बजती हैं'- पढ़ते हुए हेमिंग्वे को अपने उपन्यास का शीर्षक मिल गया क्योंकि यह पंक्तियां मानवता के आपसी संबंध व सम्पर्क को व्यक्त करती हैं और हेमिंग्वे के कार्य की महत्वाकांक्षा के अनुरूप हैं।

(लेखक प्रसिद्ध शायर और सामाजिक अध्येता हैं)

-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर

पाठक विचार मंच

ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता में हुई बढ़ोतरी

ओलंपिक खेलों में अपने देश के गौरव के लिए शब्द खेलों की शुरुआती शपथ में शामिल होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ओलंपिक खेलों की लोकप्रियता बढ़ने के साथ-साथ खेलों में राष्ट्रीय की भावना में बढ़ोतरी हुई है। आज अधिक से अधिक देश ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप काफी कठिन खेल प्रतियोगिताएं हो गई हैं। इसके लिए विकसित देशों ने भविष्य के विजेता खिलाड़ी तैयार करने के लिए स्कूली स्तर से ही एथलेटिक्स, तैराकी व जिम्नास्टिक में अतिआधुनिक खेल ढांचा अपने विद्यार्थियों के लिए तैयार कर दिया है। प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य को उच्च स्तर तक विकसित करने के लिए, स्कूल में ही शारीरिक क्रियाओं के साथ-साथ उनके पौष्टिक आहार का भी उचित प्रबंध किया होता है। जब स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी तक फिटनेस कार्यक्रम पहुंचेगा, तो वहां से विभिन्न खेलों के लिए भविष्य के खिलाड़ी मिल पाएंगे। स्कूली स्तर पर जब प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के मूलमंत्र मिलना शुरू हो जाएगी।

- आकाश, दिल्ली।